छोटे कर्ज पर सख्ती बंद करें : सीतारमण

छोटी रकम पर कठोर वसूली को बताया अमानवीय

आरबीआई की निष्पक्ष व्यवहार संहिता लागू करने की अपील

नई दिल्ली, 10 जुलाई.केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित एनबीएफसी संगोष्ठी 2025 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की ऋण वसूली प्रथाओं को निष्पक्ष, सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण बनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि ये प्रथाएं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अनुरूप होनी चाहिए.

सीतारमण ने एनबीएफसी से विशेष रूप से छोटी ऋण राशियों के मामलों में कठोर वसूली उपायों से बचने का आग्रह किया, और ग्राहक गरिमा के महत्व को याद दिलाया. उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया जिनमें 500 रुपये जैसी छोटी राशि के लिए भी कठोर वसूली कार्रवाई की खबरें आती हैं, जिन्हें उन्होंने दल दहला देने वाली कहानियां बताया. उन्होंने कहा, विकास की होड़ ग्राहक कल्याण की कीमत पर नहीं आनी चाहिए. मंत्री ने बैंकिंग क्षेत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण लक्ष्यों का समर्थन करने में एनबीएफसी की भूमिका पर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि हर साल बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण के लिए आवंटित पर्याप्त धनराशि अप्रयुक्त रह जाते हैं, जिन्हें बाद में नाबार्ड और सिडबी जैसे संस्थानों को हस्तांतरित कर दिया जाता है.

सीतारमण ने सवाल किया कि इन निधियों को वित्तीय संस्थानों को क्यों लौटाया जाना चाहिए, जबकि उन्हें जमीनी स्तर पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकता है . उन्होंने प्रस्ताव दिया कि एनबीएफसी, जो अक्सर अंतिम मील तक काम करती हैं, बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भागीदार के रूप में शामिल की जा सकती हैं . उन्होंने आरबीआई से इस साझेदारी को बिना विवेकपूर्ण मानदंडों को बाधित किए कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर मार्गदर्शन प्रदान करने का भी आह्वान किया . मंत्री ने बताया कि जब धन नाबार्ड या सिडबी में वापस आता है और फिर से जारी किया जाता है, तो वितरण में छह से आठ महीने की देरी होती है . उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लक्षित लाभार्थियों को समय पर और लक्षित ऋण वितरण सुनिश्चित करने के लिए एनबीएफसी की उपस्थिति का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए .

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता होगी तेज़

नयी दिल्ली, 10 जुलाई. भारतीय वाणिज्य मंत्रालय का एक दल प्रस्तावित व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ एक और दौर की वार्ता के लिए जल्द ही वॉशिंगटन की यात्रा करेगा. एक सरकारी अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.अधिकारी ने बताया कि इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतरिम और पहले चरण, दोनों पर बातचीत होगी.यात्रा की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि दल के अगले सप्ताह वॉशिंगटन जाने की उम्मीद है.मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय दल समझौते पर वार्ता पूरी करने के बाद इस महीने की शुरुआत में ही वॉशिंगटन से लौटा है.यह यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने अतिरिक्त आयात शुल्क को एक अगस्त तक के लिए टाल दिया है.

भारत-आसियान व्यापार समीक्षा को मिले गति

नई दिल्ली,10 जुलाई. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को आसियान के साथ मौजूदा व्यापार समझौते की समीक्षा वार्ता में तेजी लाने की उम्मीद जताई. यह मुद्दा गोयल और उनके मलेशियाई समकक्ष टी ज़ाफरुल अज़ीज़ के बीच बैठक में उठा.

पीयूष गोयल ने निष्पक्ष समझौते पर ज़ोर दिया

2025 तक समीक्षा प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य

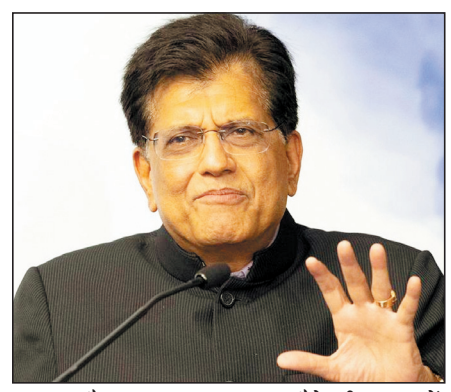

गोयल ने कहा कि मलेशिया आर्थिक मामलों पर आसियान से भारत का स्थायी समन्वयक है. मंत्रियों ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा और चुनौतियों पर चर्चा की. गोयल ने निष्पक्ष व्यापार और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ चर्चा में तेजी लाने की बात कही. उन्होंने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) पर भी आगे की चर्चा की.

यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समीक्षा वार्ता धीमी गति से चल रही है. भारतीय उद्योग लंबे समय से समझौते की समीक्षा की मांग कर रहा है. भारत एक उन्नत समझौते की तलाश में है, जो द्विपक्षीय व्यापार में मौजूदा विषमताओं को दूर कर इसे अधिक संतुलित और टिकाऊ बनाएगा.

आसियान के सदस्य ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं. भारत और आसियान के बीच वस्तुओं में मुक्त व्यापार समझौता 2009 में हस्ताक्षरित हुआ था और जनवरी 2010 में लागू हुआ. अगस्त 2023 में, दोनों पक्षों ने 2025 तक मौजूदा समझौते की पूरी समीक्षा की घोषणा की थी.

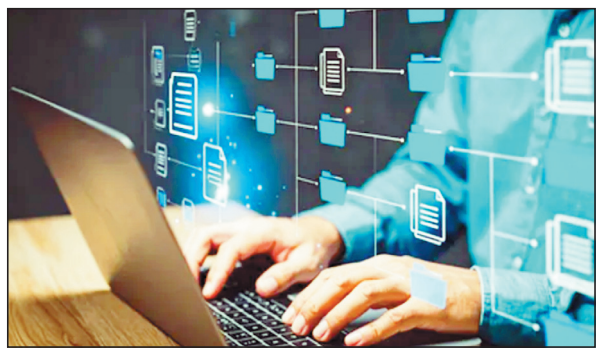

टॉप 10 टेक मार्केट में शामिल होगा भारत : रिपोर्ट

बेंगलुरु-हैदराबाद तकनीकी बाजार की मांग में अग्रणी

भारत एशिया में तकनीकी प्रतिभा का केंद्र

नई दिल्ली,10 जुलाई. कोलियर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2025 तक वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 तकनीकी बाजारों में शामिल हो जाएगा, खासकर प्रतिभा उपलब्धता के मामले में. देश के शीर्ष छह शहर पहले से ही एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तकनीकी प्रतिभा अधिग्रहण के लिए शीर्ष 10 की सूची में हैं.

एशिया प्रशांत क्षेत्र एक वैश्विक टेक टैलेंट हब के रूप में तेजी से उभर रहा है, जिसमें बेंगलुरु, टोक्यो और बीजिंग शीर्ष 10 में शामिल हैं.

कोलियर्स इंडिया ऑफिस सर्विसेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अर्पित मेहरोत्रा ने कहा कि भारत तकनीकी प्रतिभा का पावरहाउस है, जिसे कुशल प्रतिभा और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता का समर्थन प्राप्त है. भारत के प्रमुख तकनीकी शहरों में एशिया प्रशांत क्षेत्र की कुल तकनीकी प्रतिभा का 69% हिस्सा है. बेंगलुरु और हैदराबाद, जो सबसे बड़े प्रतिभा समूहों की मेजबानी करते हैं, टेक लीजिंग गतिविधि में अग्रणी हैं, और 2025 की पहली छमाही में पारंपरिक ऑफिस स्पेस की लगभग 50% मांग इन्हीं बाजारों से पूरी होगी.

भारत वैश्विक स्तर पर तकनीकी प्रतिभाओं के लिए शीर्ष गंतव्यों में से एक है . बेंगलुरु और हैदराबाद भारत में पसंदीदा तकनीकी गंतव्य बने हुए हैं, जो कुशल प्रतिभाओं और एक परिपक्व तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र वाली वैश्विक तकनीकी कंपनियों को आकर्षित करते हैं . भारत के शीर्ष सात शहरों में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उपयोगकर्ता ऑफिस स्पेस की मांग का आधार बने हुए हैं, जिसने पिछले कुछ वर्षों में पारंपरिक और फ्लेक्स स्पेस दोनों प्रकार के स्थानों में ग्रेड ए स्थान की मांग को बढ़ावा दिया है .

हीरो मोटोकॉर्प में नई शीर्ष नियुक्ति

नयी दिल्ली, 10 जुलाई.हीरो मोटोकॉर्प ने कौशल्या नंदकुमार को तत्काल प्रभाव से उभरती हुई व्यावसायिक इकाई का मुख्य कारोबार अधिकारी नियुक्त करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की.कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि इस भूमिका में वह कार्यकारी चेयरमैन पवन मुंजाल के अधीन काम करेंगी.

इसमें कहा गया, कौशल्या नंदकुमार के पास मोटर वाहन, इलेक्ट्रिक परिवहन, डिजिटल इनोवेशन और सामाजिक प्रभाव क्षेत्रों में लगभग दो दशकों का अनुभव है.कौशल्या नंदकुमार, स्वदेश श्रीवास्तव की जगह लेंगी जिन्होंने दोपहिया वाहन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी से इस्तीफा दे दिया है.

भारत को मिली स्टारलिंक की रफ्तार

सीमित कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में मिलेगी सुविधा

नई दिल्ली,10 जुलाई.एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को भारत में अपनी सेवा शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) से बुधवार को मंजूरी मिल गई है. यह अंतिम नियामक बाधा थी, जिससे स्टारलिंक के लिए देश में वाणिज्यिक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है.

मंजूरी के बाद, स्टारलिंक को अब सरकार से स्पेक्ट्रम हासिल करना होगा और अपनी सेवाओं के लिए जमीनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा. दूरसंचार विभाग सुरक्षा अनुपालन पूरा करने के लिए कंपनी को ट्रायल स्पेक्ट्रम देने को तैयार है. इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद स्टारलिंक देश में कुछ ही महीनों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू कर सकती है.

स्टारलिंक ने भारत में वीसैट प्रोवाइडर्स के साथ पहले ही व्यावसायिक समझौते किए हैं, जो विशेष रूप से सीमित स्थलीय कनेक्टिविटी वाले स्थानों के लिए उपग्रह-आधारित इंटरनेट समाधान प्रदान करते हैं. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले हफ्ते ही पुष्टि की थी कि स्पेसएक्स की स्टारलिंक सेवा के भारत में प्रवेश के लिए सभी आवश्यक जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई हैं. स्टारलिंक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अपने 6,750 से अधिक सैटेलाइट के नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है.

भारत बनेगा ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सरकार की प्राथमिकता : मल्होत्रा

ईवी रेट्रोफिटिंग और टोल छूट योजना

नई दिल्ली, 10 जुलाई. सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ग्रीन मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. भारत स्वच्छ गतिशीलता के अपने मिशन पर सही राह पर है.

इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक में मल्होत्रा ने बताया कि पीएम ई-ड्राइव और फेम-द्वितीय जैसी योजनाएं इस प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं. ईवी रेट्रोफिटिंग और टोल टैक्स छूट जैसी नीतियां परिवहन को सुलभ व टिकाऊ बनाती हैं.

उन्होंने जोर दिया कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि जलवायु लक्ष्यों, आर्थिक मजबूती और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय अनिवार्यता है. मंत्रालय द्वारा विकसित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों को अब हरित ऊर्जा और ईवी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे लागत व उत्सर्जन कम होगा, और भारत की परिवहन स्थिति मजबूत होगी.मल्होत्रा ने कहा कि मोदी सरकार 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है.

शेयर बाजार दूसरे दिन भी फिसला

मुंबई, 10 जुलाई (वार्ता)- स्थानीय शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई. प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 0.27 प्रतिशत से 0.47 प्रतिशत तक टूट गए.

विश्लेषकों के अनुसार, कंपनियों के पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी होने से पहले बाजार में सतर्कता का रुख बढ़ा हुआ है. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 345.80 अंक (0.41 प्रतिशत) गिरकर 83,190.28 अंक पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 120.85 अंक (0.47 प्रतिशत) घटकर 25,355.25 अंक पर बंद हुआ. सेंसेक्स में 24 शेयर घाटे में रहे, जबकि छह में लाभ दर्ज किया गया. लाभ में रहने वाले शेयरों में मारुति (1.36 प्रतिशत), टाटा स्टील (1.04 प्रतिशत), बजाज फाइनेंस (0.72 प्रतिशत), बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज (0.65 प्रतिशत), ट्रेंट (0.41 प्रतिशत) और टाटा मोटर्स (0.38 प्रतिशत) शामिल रहे.

घाटे में रहे शेयरों में भारती एयरटेल का भाव 2.62 प्रतिशत टूटा, जबकि एक्सिस बैंक में सबसे कम 0.02 प्रतिशत का घाटा रहा.

चांदी की कीमतों में फिर उछाल

नयी दिल्ली, 10 जुलाई. प्रतिभागियों द्वारा अपने सौदे बढ़ाने से बृहस्पतिवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 328 रुपये बढ़कर 1,07,593 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई.मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सितंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध की कीमत 328 रुपये या 0.31 प्रतिशत बढ़कर 1,07,593 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. इसमें 16,939 लॉट के लिए कारोबार हुआ.विश्लेषकों ने कहा कि प्रतिभागियों द्वारा ताजा सौदे करने से चांदी की कीमतों में तेजी आई.

मानसून का मिज़ाज बदला-बदला

बिहार, असम, आंध्र में बारिश की कमी

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में अच्छी वर्षा

नई दिल्ली, 10 जुलाई. केयरएज रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मानसून सीजन में भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है.

बिहार, आंध्र प्रदेश और असम जैसे राज्यों, जिन्होंने पिछले साल कुल खरीफ चावल उत्पादन में लगभग 15 प्रतिशत का योगदान दिया था, में सीजन की शुरुआत से ही सामान्य से कम वर्षा हुई है.

इन प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों में कमी के बावजूद, रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल मिलाकर मानसून में सुधार के संकेत दिखे हैं. देश के 36 मौसम विज्ञान उपखंडों में से 15 उपखंडों (कुल क्षेत्रफल का 43 प्रतिशत) में जून से सामान्य बारिश हुई है. वहीं, 7 उपखंडों (कुल क्षेत्रफल का लगभग 13 प्रतिशत) में कम बारिश दर्ज की गई.

समाचार विशेष

उद्धव-राज के गठबंधन ने बढ़ाई शिंदे की टेंशन

भाजपा को मिलेगा वोटर्स का अटेंशन !

मुंबई. महाराष्ट्र में 'विजय रैली' के जरिए चचेरे ठाकरे भाईयों के एक साथ आने का सबसे तात्कालिक और सीधा प्रभाव एकनाथ शिंदे खेमे पर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि इससे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत पर उपमुख्यमंत्री के दावे को नुकसान पहुंचने का खतरा है और मूल मराठी मतदाताओं के बीच उनकी स्थिति को चुनौती मिल सकती है.

बाल ठाकरे के बेटे और भतीजे के एकजुट होने के बाद शिंदे को बाहरी और गद्दार का टैग हटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं उन्हें अपने क्षेत्र ठाणे में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य शहरी इलाकों में भी असर पड़ेगा.

निकाय चुनाव पर होगा असर- गठबंधन की चर्चा नगर निकाय चुनावों से ठीक पहले जोर पकड़ रही है, जिसमें उच्च दांव वाली बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) भी शामिल है, जो शिंदे को चिंतित कर रही है, क्योंकि निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन उनके प्रभाव को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है. सार्वजनिक अपील के बजाय पर्दे के पीछे की राजनीतिक चालों के लिए जाने जाने वाले शिंदे को अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है. उद्धव और राज का मिलन शिंदे के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन में उनका प्रभाव कम होता दिख रहा है. महाराष्ट्र भाजपा के साथ शिंदे के रणनीतिक संबंध रहे हैं, लेकिन भाजपा के कई नेता उन्हें दीर्घकालिक साझेदार के बजाय अस्थायी सहयोगी के रूप में ही देखते हैं. इसके अलावा, उद्धव-राज गठबंधन भाजपा के साथ उनके पहले से ही कमजोर संबंधों को और भी खराब करने की धमकी देता है. ठाकरे की रैली से एक दिन पहले, पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने उपमुख्यमंत्री द्वारा जय गुजरात का नारा लगाए जाने को इस संभावित नए मोर्चे के बारे में उनकी चिंता के रूप में देखा गया.

क्या ठाकरे भाजपा को चुनौती देंगे?- पिछले साल विधानसभा चुनावों में राज्य की 288 सीटों में से 132 सीटें जीतने के बाद, भाजपा महाराष्ट्र में सबसे प्रमुख राजनीतिक पार्टी बनी हुई है.

भाजपा को फायदा भी हो सकता है!

एक पक्ष यह भी है कि ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने से आने से गैर-मराठी मतदाता भाजपा के पीछे एकजुट हो सकते हैं, क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की गैर-मराठी भाषियों, खासकर उत्तर भारतीय प्रवासियों के प्रति शत्रुताभाव जगजाहिर है . अगर राज विपक्ष के खेमे में शामिल होते हैं तो कांग्रेस के सामने एक नई और कहीं ज्यादा जटिल चुनौती खड़ी हो सकती है . अब तक पार्टी ने इस बारे में बहुत कम स्पष्टता के बावजूद चुप्पी साध रखी है कि ठाकरे गठबंधन के औपचारिक होने पर एमवीए अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेगा या नहीं .

राहुल-तेजस्वी ने पप्पू और कन्हैया को बताई औकात

पटना. बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ बुधवार को महागठबंधन ने बिहार बंद का आह्वान किया था. बिहार बंद को सफल बनाने के लिए दिल्ली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना पहुंचे और महज खानापूर्ति कर दो घंटों की भीतर ही दिल्ली लौट गए.

इस बीच एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई. जिस पप्पू यादव ने अपनी पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, आज उन्हें राहुल गांधी के रथ पर चढ़ने से रोक दिया गया और सुरक्षाकर्मियों ने धक्का देकर उन्हें वहा से चलता कर दिया. फजीहत झेलने वालों में सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं थे बल्कि कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया भी बेआबरू हो गए. बिहार बंद का नेतृत्व राहुल गांधी और तेजस्वी कर रहे थे.

दरअसल, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू कर दिया है. विपक्ष का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार साजिश के तहत वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करा रही है. आरोप है कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के बहाने गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश रची जा रही है. इसके खिलाफ सबसे पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पूरे बिहार में चक्का जाम करने का एलान किया था. पप्पू यादव के इस एलान के बाद कांग्रेस और आरजेडी ने पप्पू यादव के आंदोलन को झपट लिया और बिहार बंद का एलान कर दिया. तय समय पर दिल्ली से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पटना पहुंच गए.

तेजस्वी ने हिसाब बराबर कर लिया

बता दें कि यह वही पप्पू यादव हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पूर्णिया से टिकट पाने के लिए अपनी अच्छी खासी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था . पप्पू यादव और उनके बेटे ने दिल्ली में जाकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी लेकिन कांग्रेस ने कभी भी पप्पू यादव को अपनी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता नहीं माना . भले ही पप्पू यादव पार्टी का झंडा ठोते रहे लेकिन जब चुनाव आया तो लालू प्रसाद ने पूर्णिया का टिकट बीमा भारती को दे दिया और पप्पू यादव मुंह देखते रह गए थे .

शिवकुमार ने क्या प्रयास छोड़ दिया?

बेंगलुरु. कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने क्या हार मान ली है? क्या उन्होंने समझ लिया है कि वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? उनकी बातों से हताशा का अहसास हो रहा है. जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ऐलान किया कि वे पूरे पांच साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे तो इस पर टिप्पणी करते हुए शिवकुमार ने अपने बारे में कहा कि उनके पास क्या विकल्प है.

ऐसा लगा, जैसे उन्होंने इस सचाई को स्वीकार कर लिया कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे. अब उन्होंने एक दूसरी बात कही है और उससे भी हताशा ही झलकती है. पिछले दिनों वे एक मंदिर में पूजा के लिए गए थे, जहां से निकल कर कहा, 'प्रयास विफल हो सकते हैं, प्रार्थना नहीं'.

कई लोगों ने इसका मतलब यह निकाला की शिवकुमार ने मुख्यमंत्री बनने का प्रयास छोड़ दिया. लेकिन असल में ऐसा नहीं है. उनके करीबियों का मानना है कि शिवकुमार अपने बनाए टाइमलाइन पर चल रहे हैं. उन्होंने सरेंडर करने का संकेत देकर मुख्यमंत्री खेमे को तात्कालिक जीत का आनंद लेने का मौका दिया है.

विशेष | **एमआईएम को महागठबंधन का हिस्सा बनाने की बात रखी**

ओवैसी ने कांग्रेस, राजद को उलझाया

पटना. ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले करीब तीन महीने में जो राजनीति की है उससे उनकी पार्टी की और उनकी छवि में बड़ा बदलाव हुआ है. पहलगाम कांड के बाद ओवैसी ने एक राष्ट्रवादी नेता की छवि बनाई है.

उन्होंने सबसे तीखे शब्दों में पाकिस्तान की आलोचना की. इसके बाद केंद्र सरकार ने सारी दुनिया को आतंकवाद और पाकिस्तान के बारे में बताने के लिए भेजा तो एक डेलिगेशन में ओवैसी भी थे. विदेश गए डेलिगेशन में उन्होंने किसी भी विपक्षी नेता के मुकाबले बेहतर भूमिका निभाई. उन्होंने कहीं भी अपनी बात नहीं बदली. वे उसी लाइन पर

रहे, जो विदेश मंत्रालय ने तय की थी. उन्होंने इस्लामिक देशों के सामने पाकिस्तान की आलोचना की और उसे आतंकवाद फैलाने वाला देश बताया. अब उनकी पार्टी ने बिहार में एक ऐसा दांव चला है, जिससे स्थायी रूप से उनकी पार्टी की छवि बदलेगी. उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने लालू प्रसाद को चिट्ठी लिख कर कहा कि एमआईएम को महागठबंधन में शामिल किया जाए. उन्होंने लिखा कि भाजपा विरोधी वोटों का बिखराव रोकने के लिए जरूरी है कि एमआईएम गठबंधन का हिस्सा बने.

राजद की ओर से पहली प्रतिक्रिया में पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इसके लिए मना कर दिया है. उन्होंने कहा है कि ओवैसी की पार्टी को बिहार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और महागठबंधन की मदद करनी चाहिए. लेकिन ऐसे तो उनकी पार्टी कहीं चुनाव नहीं लड़ पाएगी. असल में उन्होंने राजद और कांग्रेस दोनों को उलझा दिया है. ये दोनों पार्टियां कहती रही हैं कि ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है और हर बार राजद, कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव लड़ती है. लेकिन इस बार उन्होंने अपनी ओर से तालमेल की पहल की है.